THE MINISTER OF STATE OF THE DEPTT. OF LEGAL AFFAIRS, LEGISLATIVE DEPTT. AND DEPARTMENT OF JUSTICE (SHRI RAMAKANT D. KHALAP): (a) and (b) Rule 49 of the Bar Council of India Rules provides, *inter alia*, that an advocate shall not be a full-time salaried employee of Government. This rule does not, however, apply to A "Law Officer" of Government. The Bar Council of India have issued instructions to all the State Bar Councils against enrolment of Government Servants who are not Law Officers.

विदेशी ऋणों और अनुदानों में गिरावट

327. **श्री राम जेठमलानी:** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि गत तीन वर्षों में देश को प्राप्त विदेशी ऋण एवं अनुदान आदि की राशि में निरन्तर गिरावट आयी है;

(ख) यदि नहीं, तो उपर्युक्त वर्षों के दौरान देश द्वारा प्राप्त राशि का वर्षवार ब्यौरा क्या है;

(ग) इन वर्षों के दौरान ऋणों के भुगतान की किस्त व उस ऋण के लिए ब्याज के रूप में भुगतान की गयी राशियों का वर्षवार ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या यह सच है कि 1995-96 के वित्तीय वर्ष में देश पर ऋण की राशि 1993-94 के वित्तीय वर्ष की तुलना में अधिक थी; और

(ङ) यदि हां, तो उपर्युक्त दोनों वर्षों में ऋण की राशियों की मात्रा वर्ष के अन्त में कितन-कितनी थी?

वित्त मंत्री तथा कंपनी कार्य मंत्री (श्री पी० चिदम्बरम): (क) जी, हां। पिछले तीन वर्षों के दौरान सरकारी खाते पर ऋणों और अनुदानों की कुल प्राप्तियों में गिरावट आई है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान सरकारी खाते पर मूलधन एवं ब्याज अदायगियां निम्नानुसार हैं:—

(करोड़ रुपए)

	1993-94	1994-95	1995-96
मूलधन	5079.32	5469.37	6441.04
ब्याज	3749.41	4034.93	4414.23

(घ) और (ङ) अद्यतन उपलब्ध अनुमानों के अनुसार, देश पर बकाया विदेशी ऋण की कुल राशि 31 मार्च, 1994 को 290418 करोड़ रुपए की तुलना में 30 सितम्बर, 1995 को 318319 करोड़ रुपए थी।

Reviewing of MODVAT Scheme

328. SHRI SANJAY DALMIA: Will the Minister of FINANCE be pleased to state:

(a) whether Government have reviewed the Modified Value Added Tax (MODVAT) scheme following detection of several cases of misuse of the provision which permits dealers to issue invoices for making credit claims;

(b) if so, the outcome thereof; and

(c) the action taken or proposed to be taken to prevent the misuse of this scheme?

THE MINISTER OF FINANCE AND THE MINISTER OF COMPANY AFFAIRS (SHRI P. CHIDAMBARAM): (a) The Modified Value Added Tax Scheme is being constantly monitored and reviewed and the necessary administrative and legislative steps as deemed appropriate are taken to prevent misuse of the scheme.

(b) and (c) The measures taken include registration of the dealers; maintenance of certain documents and filing of monthly return authentication of the invoice book; and penal action in case of fraud. The Government had also entrusted the study of the scheme to National Institute of Public Finance and Policy and their recommendations are under consideration.